रेजिडेंट डॉक्टरों की देशव्यापी हड़ताल

नीट परीक्षा और पीजी सेशन न होने से डॉक्टरों पर काम का दोहरा बोझ

मज़दूर मोर्चा ब्यूरो

देश के बड़े अस्पतालों में इलाज कराने दूर-दूर से आये मरीज़ों को हड़ताली डॉक्टरों की वजह से निराश होना पड़ता है तो उन्हें खलनायक नज़र आते हैं। उन्हें सारा दोष हड़ताली डॉक्टरों में ही नज़र आता है। जबकि हकीकत इसके विपरीत है। मरीज़ बेचारे अज्ञानतावश यह समझ नहीं पाते कि असल खलनायक तो पर्दे के पीछे बैठा मरीज़ों की दुर्दशा का आनंद ले रहा है।

देश भर के लाखों रेजिडेंट डॉक्टरों के संगठन फैडरेशन ऑफ़ रेजिडेंट डॉक्टर्स एशोसिएशन ने हड़ताल का यह आह्वान वेतन वृद्धि अथवा किसी आर्थिक लाभ के लिये नहीं किया है, बल्कि 56 इंची मोदी सरकार की हरामखोरी व नालायकी के विरुद्ध किया है। सरकार की इस नालायकी से न केवल डॉक्टरों का बल्कि देश भर की जनता का भी भारी नुक्शान हो रहा है। सुधी पाठकों को इस नुक्शान के बारे में गम्भीरता से समझना चाहिये।

एमबीबीएस व इसके बाद वाली पोस्ट ग्रेजुएशन (पीजी) पढ़ाई के लिये सरकार द्वारा नीट परीक्षा का आयोजन कराया जाता है। पीजी की पढ़ाई कौन लोग कर सकेंगे इसके लिये नीट परीक्षा जनवरी में आयोजित करके फ़रवरी तक इसका परीणाम घोषित कर दिया जाता है। सफ़ल हुए अभ्यार्थियों की पढ़ाई मई के महीने में शुरू हो जाया करती थी, लेकिन इस बार यह पढ़ाई अभी तक शुरू नहीं हो पाई है और न ही अगले दो महीने तक शुरू हो पाने की कोई सम्भावना है। इसका अर्थ यह हुआ कि इस महत्वपूर्ण पढ़ाई का पूरा एक साल बर्बाद हो चुका है। समझना कठिन नहीं कि इसके चलते कितने नये डॉक्टर बना पाने से देश वंचित रह गया। पीजी में दाखिला पाने के लिये देश भर के

लाखों डॉक्टर कुछ भी न करके केवल इसमें दाखिला पाने के लिये कठिन पढ़ाई करने के साथ-साथ महंगी कोचिंग भी लेते हैं।

मौजूदा मामले में देरी से हुई नीट परीक्षा का परिणाम सितम्बर माह में आ चुकने के बावजूद अभी तक पढाई तो क्या काऊंसलिंग तक भी शुरू नहीं हो सकी। कारण? सत्ता से चिपके रहने के लिये भाजपाई सरकार कुछ भी कर गुजरने को तत्पर रहती है। अपने राजनीतिक स्वार्थ के आगे उसे कुछ भी नजर नहीं आता। देशवासियों की ऐसी-तैसी भले ही हो जाये, उसे कोई चिन्ता नहीं। यूपी सहित पांच राज्यों के सिर पर खड़े चुनावों को जीतने के चक्कर में मोदी सरकार ने ओबीसी के लिये आरक्षित 15 प्रतिशत कोटे को यकायक बढ़ा कर 27 प्रतिशत कर दिया। ओबीसी कोटे का लाभ पाने के लिये उनकी आय आठ लाख रुपये वार्षिक की शर्त भी रख दी। सरकार की इस राजनीतिक धींगा-मुश्ती के विरुद्ध कुछ डॉक्टर सुप्रीम कोर्ट पहुंच गये।

कोर्ट ने सरकार से केवल इतना पूछा था कि आठ लाख की आय सीमा निर्धारित करने का आधार क्या है? 18 घंटे काम करने वाली 56 इंची मोदी सरकार ने इस सवाल का जवाब देने के लिये चार सप्ताह का समय मांगा जो मध्य अक्टूबर तक पूरा हो गया। लेकिन सरकार कोई जवाब न दे सकी। सरकार के विरुद्ध कोई कार्रवाई करने में असमर्थ उच्चतम न्यायालय ने काऊंसलिंग पर भी रोक लगा दी। जब तक सरकार जवाब नहीं देगी यह रोक जारी रहेगी। उच्चतम न्यायालय ने सुनाई की अगली तारीख 6 जनवरी 2022 रखी है।

सरकार व उच्चतम न्यायालय की इस नौटंकी के चलते अपना कैरियर बर्बाद होता देख रेजिडेंट डॉक्टरों ने पहले तो हल्का-फुल्का विरोध प्रदर्शन किया जिसका इस बेशर्म व ढीठ सरकार पर कोई असर न हुआ तो डॉक्टरों को मजबूरन हड़ताल पर जाना पड़ा। ढीठ सरकार के कान पर थोड़ी सी जूं रेंगी तो देश के स्वास्थ्य मंत्री ने हड़ताली डॉक्टरों को बुला कर दो-चार दिन में समस्या का समाधान करने का आश्वासन दे कर हड़ताल खुलवा दी। लेकिन झूठ बोलने वालों की सरकार इस मामले में भी झूठी साबित हुई तो डॉक्टर्स पुनः हड़ताल पर चले गये। इसी तरह के झूठे आश्वासन देकर स्वास्थ्य मंत्री तीन बार हड़ताल खुलवाने में सफ़ल हुए। लेकिन अब हड़ताली डॉक्टर झूठे मंत्री से बात-चीत करने को भी तैयार नहीं हैं।

पीजी के लिये काऊंसलिंग व इसकी पढ़ाई को लेकर तो अभ्यार्थी डॉक्टर संघर्ष कर ही रहे हैं, दूसरी ओर वे डॉक्टर भी संघर्ष में, सरकार द्वारा जबरदस्ती उलझा दिये गये हैं, जिन्होंने पीजी की पढाई पूरी करके परीक्षा पास कर ली है। इन डॉक्टरों को एक तरह से बंधुआ बना कर काम पर रोके रखने के लिये इनको प्रमाणपत्र नहीं दिये जा रहे। इन डॉक्टरों की हताशा का एक और बड़ा कारण कोरोना महामारी के चलते बढ़ा अतिरिक्त कार्यभार भी है। नये डॉक्टरों की खेप न आ पाने की वजह से इनका कार्य भार इतना अधिक हो गया जिसे सह पाना अब मुमकिन नहीं रहा।

कुल मिला कर डॉक्टरों की इस हड़ताल के लिये भाजपाई सरकार जिम्मेदार हैं। इसे अपनी राजनीतिक लालसा के आगे उन दुखियारे मरीज़ों का कोई दुख-दर्द नज़र नहीं आता जो सैंकड़ों मील से, किराया भाड़ा खर्च करके अस्पतालों तक आते हैं और फ़िर इलाज होने की प्रतीक्षा में अस्पतालों के बाहर इस कड़ाके की ठंड में पड़े रहते हैं।

बैंककर्मी किसानों से प्रेरित तो हुए लेकिन सबक नहीं सीखा

फ़रीदाबाद (म.मो.) बीते सात साल से अधिकांश बैंक कर्मी 'देश भक्त' बन कर मोदी भक्ति में लीन रहने के बाद जब पानी उनके सिर तक पहुंच गया तो उन्हें समझ आने लगा कि मोदी क्या चीज़ है। समझ आने के बाद भी आन्दोलन करने की हिम्मत वे कदापि न जुटा पाते यदि उन्होंने किसानों के सामने मोदी को लमलेट होते न देखा होता। लेकिन वे यह भूल रहे हैं कि किसान लाखों की संख्या में एक वर्ष तक सड़कों पर डेरा जमाये बैठे रहे थे। इस दौरान उन्होंने पुलिस दमन भी सहा और 750 से अधिक किसानों ने जान कुर्बान कर दी। वैसे आन्दोलन की शुरूआत तो जून 2020 में उसी वक्त हो गयी थी जब मोदी सरकार ने किसान विरोधी अध्यादेश जारी किया था।

दूसरी समझने वाली बात यह है कि अन्य पूर्ववर्ती सरकारों की भांति मोदी पर इस बात का कतई कोई असर नहीं पड़ता कि किसी आन्दोलन से जनता पर क्या बीत रही है। अपनी हठधर्मी एवं अहंकार के चलते उन्हें आन्दोलन को कुचल कर ही संतुष्टि मिलती है। इसे कुचलने के लिये वे साम, दाम, दंड, भेद की नीति को पूरी बेशर्मी के साथ लागू करते हैं। आन्दोलनकारियों को देशद्रोही, नक्सली, आतंकी व न जाने क्या-क्या बना देते हैं। क्या बैंक कर्मियों में यह सब 'बन' पाने की हिम्मत है? क्या वे किसानों की तरह अनिश्चितकालीन हड़ताल करने की हिम्मत रखते हैं? शायद नहीं, लगता नहीं कि बैंक कर्मी 3000 रुपये प्रति दिन का वेतन कटवा कर लम्बा संघर्ष कर पाने की स्थिति में हैं, जबकि किसान ने कभी अपने आर्थिक नुक्सान का आंकलन ही नहीं किया। किसान को न तो मकान का किराया देना था और न ही उसे महंगी शहरी जीवन शैली पर खर्च करना था।

जब किसान जाति, धर्म व क्षेत्र के भेद-भाव भूल कर संघर्ष कर रहे थे, उस वक्त बैंक कर्मी, मोदी भक्ति में लीन होकर हिन्दू-मुस्लिम की बहस का आनंद ले रहे थे। पाकिस्तान को सबक सिखाने से रोमांचित हो रहे थे। धारा 370 व राम मंदिर की धुन में मद-मस्त थे। पानी उनके सिरों तक यकायक नहीं पहुंच गया, पहले घुटने तक, फ़िर कमर तक और छाती तक आने के बाद सिर तक पहुंचा है। क्या उन्हें संकट का आभास उस वक्त नहीं हुआ था जब जन-धन खाते खोलने के नाम पर उन्हें बेजा बोझ से लाद दिया गया था? नोट बंदी के वक्त जब ये लोग गधों की तरह रात के आठ-दस बजे तक बैंकों में अपनी ऐसी-तैसी कराते देश भक्त बने मोदी के गीत गा रहे थे? और यह सब उस वक्त होता रहा जब तमाम बैंको में स्टाफ़ की घोर कमी चल रही थी। सरकार द्वारा बैंकों को लुटवाने के बाद क्षतिपूर्ति के लिये स्टाफ़ का वेतन बिल घटाने के मकसद से भर्तियां रोक दी गयी थीं। बैंक जब लुट रहे थे उस वक्त इन कर्मियों का संगठन कहां सो रहा था?

घाटे में डूबते बैंकों के अलावा मुनाफ़े में चलने वाले बैंकों को भी बड़े बैंकों को मिला कर जब सरकार अपनी दादागिरी दिखा रही थी, उस वक्त बैंक यूनियन क्यों नहीं संघर्ष पर उतरी? आज, जब मोदी सरकार पूरी तरह से हावी हो चुकी है तो बैंक कर्मी उससे लड़ाई लड़ने उतरे हैं, वह भी गत्ते की बनी नकली तलवार हाथ में लेकर! इनका नेतृत्व प्रबन्धन की दलाली करते-करते इतना सुविधाभोगी हो चुका है कि वह संघर्ष करना ही भूल चुका है। ऐसे नेतृत्व के भरोसे जो आज भी मोदी की अंधभक्ति में लीन हो, यह लड़ाई नहीं जीती जा सकती। हां, यदि वास्तव में ही जंग जीतनी है, अपने व देश के हितों के लिये तो लम्बी लड़ाई व कुर्बानी के लिये तैयार हो जायें। नेतृत्व में काबिज अंधभक्त रूपी काली भेड़ों को निकाल बाहर किया जाय, वरना कुछ हासिल होने वाला नहीं।

खबर मरम्मत

– जुम्मन मियां पंक्चर वाले

अरब में खुलेपन की बयार और भारत में 'संस्कृति' की मार

संयुक्त अरब अमीरात में खुलेपन की बयार का बहना जारी है। शराब पर प्रतिबन्ध ढीला करने, साप्ताहिक अवकाश रविवार को करने और अविवाहित युवाओं को साथ रहने की अनुमति देने के बाद वहां की सरकार ने अब निर्णय लिया है कि फ़िल्मों पर नियंत्रण को ढीला किया जायेगा। इसके अन्तर्गत 21+ नाम से एक नया वर्ग बनाया जायेगा जिसमें अन्तर्राष्ट्रीय फ़िल्मों को बिना कोई सीन काटे यों का यों प्रदर्शित किया जा सकेगा।

दूसरी तरफ़ भारत है जहां जरा-जरा सी बातों पर न सिर्फ़ हंगामा करके फ़िल्में और अन्य अभिव्यक्ति के साधनों पर प्रतिबन्ध लगाये और बढाये जा रहे हैं बल्कि संस्कृति के नाम पर समाज को 16 वीं शताब्दी की ओर धकेला जा रहा है। संस्कृति और परम्पराओं के नाम पर ही युवाओं को विवाह पूर्व मिलने से रोका जा रहा है, विवाह पूर्व साथ रहने की तो बात ही छोड़ दीजिये।

स्वर्ण मन्दिर में धर्म और हत्या

स्वर्ण मन्दिर, अमृतसर में बीते शनिवार को धार्मिक पुस्तक को अपवित्र करने के मामले में हुई हत्या के मामले में पुलिस ने मृत व्यक्ति पर ही धर्म-स्थान को अपवित्र करने का केस दर्ज करने का फ़ैसला किया है। हालांकि खुद पुलिस के अनुसार प्रथम दृष्टया यह एक चोरी का मामला दिखता है क्योंकि गृभग्रह में गुरू ग्रन्थ साहिब समेत किसी भी वस्तु से छेड़-छाड़ नहीं की गयी पायी गयी है।

भारत में लगातार बढ़ती धार्मिक कट्टरता और असहिष्णुता के आगे गरीब का खून पानी की तरह बहाया जा रहा है। धार्मिक स्थानों को अपवित्र करने पर कानूनन कार्रवाई होनी चाहिए लेकिन किसी धर्मग्रन्थ को अपवित्र करने के आरोप पर किसी की हत्या कर देना कहां तक उचित है? क्या यह धर्मग्रन्थ जिस प्रेस में छपे होंगे वहां ऐसे ही पवित्रता के नियमों का पालन किया गया होगा?

दिल्ली में दारू का टोटा, हरियाणा में पीने वालों का

दिल्ली में नयी एक्साइज पॉलिसी लागू हो गयी है लेकिन इसके तहत खुलने वाली 850 में से 500 दुकानें अभी तक नहीं खुल पायी है। कारण अनेक हैं। कुछ स्थानीय लोगों के विरोध के कारण, तो कुछ निर्माण कार्य पर बैन लगा होने के कारण, तो कुछ ट्रकों पर बैन लगा होने के कारण नयी दुकान या तो निर्मित नहीं हो सकी या उनमें सामान नहीं पहुंच पाया है। इस कारण से आम आदमी के लिये दिल्ली में दारू की अत्यधिक कमी हो गयी है। ऐसे में बेचारे दिल्ली के प्यासे लोग अपनी प्यास बुझाने के लिये, फ़रीदाबाद, गुड़गांव और नोयडा के चक्कर लगाने को मजबूर हैं।

ऐसी भयंकर सर्दी में दारू की कमी निश्चित ही मदिराप्रेमियों पर एक भारी अत्याचार है। पर आश्चर्य है कि जिस बोतल को ले दे कर सारे काम हो जाया करते हैं खुद उसी का काम ले-देकर भी नहीं हो पा रहा है। क्या वास्तव में घोर कलियुग आ गया है? दूसरी तरफ़ हरियाणा में सरकार ने शराब पीने की उम्र 25 से घटाकर 21 साल कर दी है। जैसे कि 21 साल वाले अभी तक सरकारी आदेश के इन्तजार में प्यासे ही बैठे थे या हरियाणा सरकार को पीने वालों का टोटा महसूस हो रहा था!

अन्तिम मिसरा

क्या शादी की उम्र 18 से 21 साल करने से जो लड़कियां पढ़ाई छोड़ शादी कर लेती थी वो अब शादी छोड़ पढाई करेंगी!

प्रकाशक, मुद्रक एवं संपादक सतीश कुमार ने अपने स्वामित्व में एजीएस पब्लिकेशन्स, डी-67, सैक्टर-6, नोएडा से मुद्रित करवा कर 708 सैक्टर-14 फरीदाबाद से प्रकाशित किया। Postal Reg. No. L/H.R/FBD/463-06